उद्योगों के लिए भूमि होगी और सस्ती

लीज रेंट घटाने की तैयारी मेरठ के खेल उद्योग की तर्ज पर विकसित होंगे क्लस्टर

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि और सस्ती की जाएगी। साथ ही लीज रेंट को कम किया जाएगा। सरकार अलग-अलग श्रेणी के उद्योगों के लिए मेरठ के खेल उद्योग की तर्ज पर अलग-अलग क्लस्टर विकसित करेगी। वहीं औद्योगिक भूमि के आवंटन में स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योगों के लिए नीलामी की बजाय लाटरी के जरिए भूखंडों का आवंटन करने की भी नीति तैयार की जा रही है।

बुधवार को औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर औद्योगिक सुधारों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को और सरल बनाने की रणनीति तय की गई। बैठक में नन्दी व एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश को और गति प्रदान करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूखंड उपलब्ध कराने के नियम और शर्तों को एक समान बनाया जाए। भूखंड के हस्तांतरण की व्यवस्था को

- भूमि आवंटन में स्टार्टअप और एमएसएमई को मिलेगी प्राथमिकता
- नीलामी की बजाय लाटरी से किया जाएगा भूखंडों का आवंटन

समाप्त कर आवंटित भूमि का उपयोग केवल उद्योगों स्थापना के लिए होना चाहिए। ऐसा न करने वालों के भूखंडों का आवंटन रद किए जाए। बैठक में यह भी प्रस्तावित किया गया कि सूक्ष्म उद्यमियों को कम किस्तों पर शेड उपलब्ध कराकर प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित की जाए।

मंत्रियों ने इस बात पर सहमति दी है कि उद्योगों के लिए आवंटित भूमि पर लीज रेंट न्यूनतम हो। यदि भूखंड सरकारी भूमि पर हो तो उद्यमियों से केवल विकास शुल्क लिया जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि किराए के स्थानों पर चल रहे उद्योगों और इकाईयों के विस्तार के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाए।

गीडा के स्थापना दिवस पर होगा 134.15 करोड़ का निवेश

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के स्थापना दिवस पर 30 नवंबर को 134.15 करोड़ रुपये के निवेश वाली 38 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 नवंबर को तीन दिवसीय स्थापना दिवस समारोह और राज्य स्तरीय व्यापार मेले का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पांच निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा 123.82 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार 33 इकाईयों का लोकार्पण किया जाएगा। गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुज मलिक ने बताया कि गीडा ने वर्तमान वर्ष में 116 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निवेशकों को किया है। इन भूखंडों पर करीब 6,139 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 11,072 लोगों को रोजगार मिलेगा। समारोह के दौरान गीडा द्वारा विकसित किए जा रहे विभिन्न औद्योगिक सेक्टरों में बुनियादी विकास के 114 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इनमें सड़क, नाली, पुलिया व बिजली से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए 61.27 करोड़ रुपये स्वीकृत

जनरल विपिन रावत रक्षा औद्योगिक गलियारा झांसी नोड में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए शासन ने 61.27 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से आंतरिक सड़कों एवं जल निकासी के चालू कार्य को पूरा कराया जाएगा। 1086.17 हेक्टेयर में स्थापित हो रहे इस नोड में भारत डायनमिक्स लिमिटेड ने 400 करोड़ और एयरोलाय टेक्नालाजीज ने 320 करोड़ रुपये के निवेश से टाइटेनियम कास्टिंग का उत्पादन शुरू किया है। वहीं स्वीडन की कंपनी साब एबी दो हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। साब एबी सेना के लिए हल्की तोप व मिसाइलों का निर्माण करेगी। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अन्य कंपनियों को भी भूमि आवंटित की जा चुकी है।

पूरी खबर पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें